जल जीवन मिशन, PWD ने करोड़ों किए बर्बाद

कैग की रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताएं उजागर

■ नागपुर, बिजनेस रिपोर्टर. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की मार्च 2024 की अवधि तक के लिए वर्ष 2026 की अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न विभागों में वित्तीय प्रबंधन, परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं में गंभीर खामियां सामने आई हैं. रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण (महा-कैंपा), महाराष्ट्र में केंद्र की महत्वाकांक्षी ग्रामीण पेयजल योजना जल जीवन मिशन की योजना, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा विमानन परिवहन संचालनालय में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं, व्यर्थ खर्च और नियमों का उल्लंघन हुआ है. कैग ने अपनी रिपोर्ट में इन सभी मामलों में संबंधित विभागों को प्रक्रियाओं में सुधार, वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मजबूत करने की सिफारिश भी की है. रिपोर्ट के अनुसार महा-कैंपा द्वारा वार्षिक कार्ययोजना के दायरे से बाहर 94.69 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया. वहीं उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण को राशि समय पर हस्तांतरित नहीं किए जाने से 40.80 करोड़ रुपए के ब्याज का नुकसान हुआ है. वहीं गोरेवाड़ा प्राणी संग्रहालय के रेस्क्यू सेंटर के लिए 5.50 करोड़ रुपए का वितरण सीएएफ नियम, 2018 के विपरीत पाया गया, जबकि निधि निकासी की सीमा निर्धारित नहीं होने से 2.55 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बैंक शुल्क वहन करना पड़ा. रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि 15 वन विभागों में प्रतिपूरक वनीकरण की परियोजनाएं समय पर स्वीकृत नहीं होने से केवल 47.37 प्रतिशत भौतिक लक्ष्य ही पूरे हो सके और स्वीकृत निधि का केवल 42.48 प्रतिशत खर्च किया जा सका.

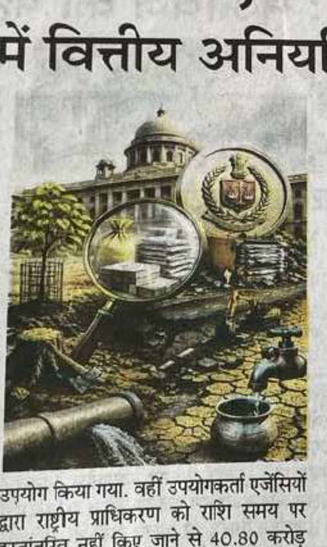

पीडब्ल्यूडी में 21.73 करोड़ का अनियमित वितरण

सार्वजनिक निर्माण विभाग में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अनुमान और तकनीकी स्वीकृति के लिए प्राप्त 21.73 करोड़ रुपए के शुल्क का अनियमित वितरण किया गया. वहीं अनुबंध में प्रावधान नहीं होने के बावजूद कार्य शीघ्र पूरा करने के नाम पर ठेकेदारों को 1.34 करोड़ रुपए का बोनस दे दिया गया.

'सेवा स्तर समझौते' की शर्तों का पालन नहीं

- ☐ रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि विमानन परिवहन संचालनालय में एच-145 हेलिकॉप्टर के रखरखाव, मरम्मत और निरीक्षण एजेंसी की नियुक्ति में देरी के कारण 2.07 करोड़ रुपए का ऐसा व्यय हुआ जिसे टाला जा सकता था.
- ☐ 'कैग' ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा में भी कई कमियां दर्ज की हैं. रिपोर्ट के अनुसार सेवा स्तर समझौते की प्रमुख शर्तों का पालन नहीं किया गया.
- ☐ 2 स्तरीय प्रमाणीकरण, पासवर्ड नीति, उपयोगकर्ता प्रबंधन, डेटा सुरक्षा तथा सॉफ्टवेयर नियंत्रण में कमियां पाई गईं जिससे प्रणाली की सुरक्षा और वित्तीय नियंत्रण प्रभावित होने की आशंका रिपोर्ट में जताई गई है.

गलत चयन, नहीं हो पाया वनीकरण कार्य

इसके अलावा 2,592.73 हेक्टेयर भूमि पर गलत चयन के कारण वनीकरण कार्य नही हो पाया तथा 5,727.243 हेक्टेयर गैर-वन भूमि को आरक्षित अथवा संरक्षित वन घोषित नहीं किया जा सका. महाराष्ट्र मे केंद्र की महत्वाकांक्षी ग्रामीण पेयजल योजना जल जीवन मिशन की योजना के संबंध मे रिपोर्ट में कहा गया है कि सांगली जिले के आटपाडी तहसील के 53 गांवों की समूह जलापूर्ति योजना मे त्रुटिपूर्ण सर्वेक्षण रिपोर्ट के कारण 94.39 करोड़ रुपए का व्यर्थ खर्च हुआ और परियोजना अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी है. इसी तरह बीड़ जलापूर्ति योजना मे विद्युत बकाया के कारण पंपिंग मशीनें निष्क्रिय रहीं जिससे 97.28 लाख रुपए का खर्च व्यर्थ चला गया.

सलि

राकां :
सौंपा

■ नागपुर,
शरदचंद्र पवार
जिप सदस्य
आधिकारिक
अध्यक्ष नियुक्त
के वरिष्ठ नेता
ने उन्हें नियुक्ति
संगठन को
बनाने के लि
जिलाध्यक्ष प
सलिल देशमु
पवार, प्रदेश
सांसद सुप्रि
मंत्री अनिल
वरिष्ठ नेता
नियुक्ति प
शरद पवा
मुलाकात
राकां में
चुके हैं.
सक्रिय क
के रूप

डेंट कर पुलिस को धमकी

फफूंद लगी और एक्सपायरी खाद्य सामग्री नष्ट, एफडीए की बड़ी कार्रवाई

स्पा एंड सैल

2 पीड़ित महिला

ents to provide comfort and
otional security. When child-

parent's love that they never truly receive.

forms part of a
wider national crackdown on Shahzad Bhatti's syndicate. Similar ac-

in Maharashtra. Auth
urged citizens to stay vi
port any suspicious onli

urns
amp

ptly stopped
lanation. As
derate rain-
chamber to
ing the sur-
h contami-

the autho-
he monso-
ent solu-
d. Every
he locali-
ip," said
e signa-
t.
Sanjay
gnant
eding
toes.
ople
fe-
na-
wa-
ro-
di-

en-
ng
ng

₹5.5-Crore Gorewada Rescue Centre funding faulty: CAG

Abhishek.Choudhari@timesofindia.com

GOREWADA RESCUE CENTRE

Nagpur: The Comptroller and Auditor General (CAG) flagged ₹5.50 crore disbursed to the Forest Development Corporation of Maharashtra (FDCM) for a rescue centre at Nagpur's Gorewada Zoo as irregular expenditure made in violation of afforestation fund rules, in a report presented to the state legislature on Friday.

The amount was released by Maharashtra Compensatory Afforestation Management and Planning Authority (Maha CAMPA) during 2021-22 and 2022-23 for setting up the rescue centre, in violation of the Compensatory Afforestation Fund (CAF) Rules, 2018, according to the CAG compliance audit report for the period ended March 2024.

*The Gorewada disbursement was part of a wider set of irregularities the audit found in the functioning of Maha CAMPA, the body that manages funds collected for com*pensatory afforestation when forest land is diverted for non-forest use.

The CAG flagged the irregular diversion of ₹94.69 crore of CAMPA funds for execution of budgeted schemes, with implementing agencies unauthorisedly executing works not included in the Annual Plan of Operation (APO).

The audit found that compensatory afforestation achieved only 47.37% of planned activities and utilised only 42.48% of the approved amount, owing to delays in the preparation, submission and approval of the APO. In 60 projects across 11 divisions, against 4,168.01 hectares of forest land diverted, afforestation to the extent of 3,777.33 hectares was carried out on forest land instead of non-forest land as envisaged.

Winter se
begin in
from Dec

Nagpur: The
Legislature's ne
sion will comm
pur on Dec 7, As
ker Rahul Narw
ced on Friday aft
sion of the mon
which ended wi
nal anthem aft
spanning 127 ho
nutes of busines
The Assemb
hours and 9 mi
each day durin
Narwekar said
ting the House's
A total of 9
were received d
sion. Of these, 4
ted, with mini
to 58 orally in
500 through wr
Assembly a
the six notice
short-duration
of which 3 were